SPECIAL MENTIONS

Demand to declare extreme heat as a natural disaster

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश) : सर, भारत में इस वर्ष भीषण गर्मी का सबसे लंबा दौर रिकॉर्ड किया गया है और देश में 536 heat-wave days रहे हैं, जो 14 सालों में सबसे ज़्यादा हैं। इस वर्ष भारत में भीषण गर्मी के कारण 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और heat stroke के 40,000 से संदिग्ध मामले report किये गए हैं, जो एक चिंताजनक आंकड़ा है। भीषण गर्मी के कारण हो रहे नुकसान का संज्ञान संयुक्त राष्ट्र ने भी लिया है और इसे महामारी का रूप भी बताया है, जिसके कारण पूरे विश्व में हर वर्ष 5 लाख से अधिक लोगो की मृत्यु हो रही है, जो बाढ़ और तूफ़ान जैसी प्राकृतिक आपदा से होने वाली मृत्यु से भी ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी सभी देशों को इसके प्रति जागरूक होकर कार्य करने का निवेदन किया है। RBI के अनुसार Global warming और भीषण गर्मी के कारण देश की GDP को 2.8 प्रतिशत तक का नुकसान होने का अनुमान है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण के लिए the Disaster Management Act है, लेकिन इस कानून के अंतर्गत अभी तक भीषण गर्मी या heat-wave को natural disaster नहीं घोषित किया गया है।

(Mr. Deputy Chairman *in the Chair.*)

मेरा सरकार से निवेदन है कि भीषण गर्मी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे natural disaster घोषित किया जाए, जिससे सरकार भीषण गर्मी से हो रही क्षति के प्रबंधन में और बेहतर ढंग से कार्य कर सके।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Spetial Mention raised by hon. Member, Shri Sanjay Seth: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar) and Shri Haris Beeran (Kerala).

Concern over Ayushman Bharat Scheme

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब) : महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है। आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत अभी तक 55 crore नागरिकों और 12.34 crore परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है, इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को बीमा की सुविधा दी जाती है। हमारे देश में कैंसर cases की बढ़ोतरी हो रही है और यह अनुमान है कि 2025 तक हर वर्ष भारत में 16 लाख कैंसर cases होंगे और economic survey ने यह कहा है कि India's out-of-pocket expenses on healthcare are over 50 per cent of the total health expenses, जो एक चिंता का विषय है,

क्योंकि cancer हो, heart disease हो, road accidents हों, Lifestyle diseases हों, इन सभी के उपचार का खर्चा बहुत ज़्यादा है, जो 5 लाख की राशि में नहीं हो सकता। आज की महंगाई और cost of treatment देखते हुए यह अत्यंत ज़रूरी है कि one-size-fits-all approach को बदलना होगा। हमारे देश का जो बुज़ुर्ग या वरिष्ठ नागरिकों का वर्ग है, उन्हें आज भी किसी प्रकार का बीमा या social security नहीं दी जाती है। बीमा कंपनी भी वरिष्ठ नागरिकों को बीमा देने से मना कर देती है। मेरी मांग है कि सरकार सबसे पहले आयुष्मान भारत में दिए जाने वाले बीमा को disease-specific करे और बीमा की राशि को बढ़ाया जाए और इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत शामिल करके उन्हें social security net के अंतर्गत लाया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. associated themselves with the Special Mention raised by the hon. Member, Dr. Ashok Kumar Mittal: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Sanjeev Arora (Punjab), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), and Shri Jawhar Sircar (West Bengal).

Inclusion of 'Ahimsa' (Non-Violence) in the Preamble of the Indian Constitution

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to seek the inclusion of 'Ahimsa' (non-violence) in the Preamble of the Indian Constitution. Former hon. Chief Minister of Odisha, in May 2018, during the first meeting of the National Committee for 150th Birth Anniversary Celebrations of Mahatma Gandhi, had requested for inclusion of 'Ahimsa' in the Preamble of the Indian Constitution. He had again, in December 2019, reiterated this demand in second meeting of the National Committee for celebrations of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi. On 23rd March, 2021, Odisha Vidhan Sabha passed a unanimous resolution for inclusion of 'Ahimsa' in the Preamble of the Indian Constitution. On the same day, the Odisha Assembly also had a three-hour special discussion on Gandhi*ji*'s visit to Odisha exactly 100 years back on 23rd March, 1921. Apart from hon. Chief Minister of Odisha's iteration and Odisha Vidhan Sabha's resolution, signature campaign across the State for inclusion of 'Ahimsa' in the Preamble of the Constitution of India also took place. On the occasion of 75 years of India's Independence, hon. former Chief Minister of Odisha also flagged off the *Ahimsa Rath*, whose sole objective was to spread the Gandhian doctrine of 'Ahimsa' (non-violence)across the cross-sections of the people and commemorating Gandhi*ji*'s special relation with Odisha. Placing these initiatives on record, I reiterate the request that the Government of India may